RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 04 MAY 2022 TO 10 MAY 2022 प्रति बुधवार वर्ष 07 अंक 34 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

रिसर्च में हुआ खुलासा, हवा के जरिए भी कोरोना वायरस के कण फैला सकते हैं संक्रमण Page 5

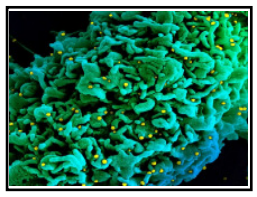

तुलसी की सूखी पत्तियां चमकाएंगी आपका भाग्य, उन उपायों से मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न Page 6

बीएमडब्लू ग्रुप इंडिया का इंडिया आर्ट फेयर में 'फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी' का प्रदर्शन Page 7

editoria!

कटौती की आहट

देश में जहां तापमान बढ़ने से चिंता बढ़ी है, वहीं बिजली की खपत भी रिकॉर्ड स्तर पर है। अभी तक जो स्थिति है, उसे बहुत चिंताजनक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। राज्य सरकारों को संयम रखना चाहिए, लेकिन संकट की आशंका से कुछ राज्य सरकारें ज्यादा चिंतित हैं। एक सवाल यह पैदा हो गया है कि क्या देश में कोयले का अभाव होने लगा है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सीईए) की डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक, 165 ताप विद्युत घरों में से 56 में 10 प्रतिशत या उससे कम कोयला बचा है। कम से कम 26 के पास पांच फीसदी से कम कोयला भंडार बचा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी ऊर्जा संकट और कोयले के अभाव के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया है। पर इसके जवाब में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) का बयान खास मायने रखता है। एनटीपीसी ने कहा है कि उसके पास कोयले की कमी नहीं है। दरअसल, भीषण गरमी की वजह से राजधानी दिल्ली में बिजली की मांग अप्रैल महीने में पहली बार 6,000 मेगावाट प्रतिदिन के स्तर को पार कर गई है। पूरे देश में बिजली की बढ़ी हुई मांग को समझने के लिए यह एक मिसाल ही काफी है। भारत में भीषण गरमी के चलते छह साल से अधिक समय में सबसे विकट बिजली की कमी देखी जा रही है। चूंकि भारत में विद्युत उत्पादन ज्यादातर कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों में होता है, इसलिए कोयले की मांग बहुत बढ़ गई है। कोयले का भंडार कम से कम नौ वर्षों में सबसे कम पूर्व-ग्रीष्मकालीन स्तर पर है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, भारत में ऊर्जा की मांग रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। आपूर्ति में कमी नहीं आई है, लेकिन मांग बढ़ गई है। कमी दो प्रतिशत भी नहीं है, लेकिन असर कुछ राज्यों में दिखने लगा है। जम्मू-कश्मीर से आंध्र प्रदेश तक दो घंटे से लेकर आठ घंटे तक की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में अभी विशेष कटौती नहीं हो रही है और न उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी परेशानी सामने आई है। लेकिन संकट आगे न बढ़े, इसके लिए पूरे इंतजाम की जरूरत है। आम लोगों को भी अपने-अपने स्तर पर जरूरी बिजली का ही उपयोग करना चाहिए, यह वाजिब सलाह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दी है। देश में ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार प्रमुख उपक्रम एनटीपीसी ने आश्वस्त करने की कोशिश की है, लेकिन तब भी सचेत रहना समय की मांग है। गरमी जैसे-जैसे बढ़ेगी, बिजली की मांग में भी अप्रत्याशित वृद्धि होगी। समस्या के बढ़ने से पहले ही समाधान सुनिश्चित कर लेना चाहिए। गौर करने की बात है कि कोयले की आपूर्ति अबाध करने के लिए अनेक ट्रेनों के संचालन को रोका गया है। इसका मतलब केंद्र सरकार गंभीर है। इसमें कोई शक नहीं, कोयले के अभाव की वजह से संकट खड़ा हुआ, तो केंद्र सरकार को ही आलोचना झेलनी पड़ेगी। रेलवे कोयले के परिवहन के लिए युद्धस्तर पर कदम उठाने की कोशिश कर रहा है और कोशिश में है कि कोयला बिजली संयंत्रों तक पहुंचाने में कम समय लगे। ट्रेनों के रद्द होने से भी संकट की गंभीरता का अंदाजा होता है। जिन लोगों की यात्रा प्रभावित होगी, उनके बारे में भी सोच लेना चाहिए। बिजली क्षेत्र की जरूरतों को युद्ध स्तर पर पूरा करना चाहिए। बिजली सबको चाहिए, तो इसके लिए सबको सोचना भी पड़ेगा।

रूस से तेल पर डिस्काउंट चाहता है भारत

शर्त मानी तो होगा बंपर फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

मिडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक रूस से भारत की सरकारी और निजी दोनों रिफाइनर ने फरवरी के अंत में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से 40 मिलियन बैरल से अधिक रूसी क्रूड ऑयल खरीदा। यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा रूस अपने तेल को बेचने के तमाम प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में वह भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल बेचने की पेशकश पहले ही कर चुका है क्योंकि अन्य खरीदार रूस से मुंह मोड़ चुके हैं। ऐसे में भारत तेल के ध्ईंप्ट्रि प्रोड्यूसर के साथ डील करने के जोखिम की भरपाई के लिए रूसी तेल पर गहरी छूट पाने की कोशिश कर रहा है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा है कि इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। नाम न छापने की शर्त पर लोगों ने कहा कि भारत रूस से डिलीवर किए गए तेल के आधार पर प्रति बैरल 70 डॉलर (5352 रुपये) से कम पर रूसी तेल खरीदना चाहता है। बता दें कि वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट फिलहाल 105 डॉलर (8028 रुपये) प्रति बैरल के करीब बिक रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक रूस से भारत की सरकारी और निजी दोनों रिफाइनर ने फरवरी के अंत में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से 40 मिलियन बैरल से अधिक रूसी क्रूड ऑयल खरीदा है। व्यापार मंत्रालय द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे 2021 की तुलना में रूस-से-भारत के लिए तेल खरीद 20% अधिक है।

भारत अपने 85% से अधिक तेल का आयात करता है और रूसी कच्चे तेल के कुछ शेष खरीदारों में से है। वहीं तेल व्लादिमीर पुतिन के शासन के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। यूरोपीय मांग का काम होना रूस के तेल उद्योग पर गंभीर दबाव डाल रहा है, सरकार का अनुमान है कि इस साल उत्पादन में 17% तक की गिरावट आ सकती है।

भारत में रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन समुद्री बीमा जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को कड़ा करने और अमेरिका द्वारा नई दिल्ली पर दबाव के चलते रूस के साथ व्यापार कठिन बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक भारी छूट वाले तेल प्राप्त करने के अवसर के कारण मास्को के साथ अपने संबंधों को कम करने के लिए पश्चिमी दबाव का विरोध किया है। भारत रूसी हथियारों के आयात पर भी अत्यधिक निर्भर है।

सूत्रों ने कहा कि अगर रूस भारत द्वारा बताई गई कीमतों पर सहमत होता है और भारत को तेल डिलीवर करता है, तो भारत के सरकारी रिफाइनर एक महीने में लगभग 1.5 मिलियन बैरल ले सकते हैं - जोकि कुल आयात का दसवां हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार से जुड़े प्रोसेसर किसी भी संभावित समझौते से लाभान्वित होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसे निजी रिफाइनर आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से अपना फीडस्टॉक खरीदते हैं।

प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार मिलने पर

आईपीपीएफ ने कलेक्टर का स्वागत और किया अभिनंदन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

प्लास्टिक और पैकेजिंग उद्योगों की प्रतिनिधी संस्था इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के प्रतिनिधिमंडल ने इन्दौर कलेक्टर श्री मनीषसिंह से उनके कार्यालय में भेंट की। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के माध्यम से जन आंदोलन को बढ़ावा- जनभागीदारी के लिए उन्हें मिले प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए इनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। इन्दौर में स्वच्छता के मॉडल के लिए प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार कलेक्टर मनीष सिंह को नागरिकों के कल्याण में शानदार काम करने के लिए प्रदान किया गया है। आईपीपीएफ के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल के नेतृत्व में प्रबंध समिति के सदस्यों के ने कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी।

अध्यक्ष श्री बंसल ने बताया कि कलेक्टर श्रीमनीष सिंह के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के लिए मिले

प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए फोरम की ओर से एक अभिनंदन पत्र देकर उनका अभिनंदन व स्वागत किया गया। उन्हें इन्दौर का नाम देश ही नही विदेशों में भी लगातार स्वच्छता में प्रथम आने वाले शहर के रूप में लाने के लिए भी साधुवाद भी दिया। आईपीपीएफ के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के साथ प्रस्तावित प्लास्टिक कलस्टर औक औद्योगिक क्षेत्रों की विविध समस्याओं पर भी चर्चा की। इस दौरान प्लास्टिक कलस्टर की स्थापना के लिए अभी तक किए गए प्रयासों के साथ जल्दी ही जमीन आवंटन और विकास कार्य को मुर्त रूप देने पर भी चर्चा की गई। श्री सिंह ने इसके लिए सभी प्रकार की मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान फोरम के कार्यकारणी सदस्य और उद्योगपति उपस्थित थे। इसमें वरिष्ठ सदस्य सुभाष चर्तुवेदी, प्रेमनारायण नागौरी, सचिव राम किशोर राठी, उपाध्यक्ष मेहूल ठक्कर, कोषाध्यक्ष जाहिद खान, संजीव सचदेवा आदि उपस्थित थे।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक की मुख्य बातें

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति की बिना तय कार्यक्रम के आयोजित बैठक में लिए गए मुख्य फैसले:

- नीतिगत दर (रेपो) को तत्काल प्रभाव से 0.40 प्रतिशत बढ़ाकर 4.4 प्रतिशत किया गया।
- अगस्त, 2018 से नीतिगत दर में पहली बढ़ोतरी, कॉरपोरेट और आम लोगों के लिए उधार की लागत बढ़ेगी।
- नकद आरक्षित अनुपात को 0.50 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत किया गया, 21 मई से प्रभावी।
- एमपीसी ने दो मई और चार मई को बिना तय कार्यक्रम के बैठक आयोजित कर मुद्रास्फीति की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया।
- आरबीआई ने उदार नीति बनाए रखने का फैसला किया। साथ ही महंगाई को लक्ष्य के भीतर रखने के लिए उदार रुख को धीरे-धीरे वापस लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- वैश्विक जिंस कीमतों के चलते भारत में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है।
- प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लॉकडाउन और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी व्यवधान से लॉजिस्टिक लागत बढ़ सकती है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक परिस्थितियों में गिरावट का सामना करने में सक्षम है।
- उर्वरक की कीमतों में उछाल और अन्य लागत का भारत में खाद्य कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- वैश्विक स्तर पर गेहूं की कमी से घरेलू कीमतें प्रभावित हो रही हैं, भले ही घरेलू आपूर्ति पर्याप्त बनी रहे।
- एमपीसी की अगली बैठक 6-8 जून को होगी।

मुंबई के प्रमुख कार्यालय भवनों में पानी आधारित वातानुकूलन से हर साल बच सकते हैं 175 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली। एजेंसी

मुंबई के प्रमुख कार्यालय भवनों में यदि हवा आधारित केंद्रीकृत वातानुकूलन (कूलिंग) प्रणाली की जगह पानी आधारित वातानुकूलन को अपनाया जाए, तो हर साल बिजली के बिल में 175 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। जेएलएल इंडिया ने बुधवार को यह बात कही। संपत्ति सलाहकार ने कहा कि इस समय मुंबई में 'ए' श्रेणी के कार्यालय स्थल का कुल क्षेत्रफल 14.4 करोड़ वर्ग फुट है। इसमें से सिर्फ 42 प्रतिशत (छह करोड़ वर्ग फुट) केंद्रीकृत हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। एचवीएसी को आम बोलचाल की भाषा में वातानुकूलन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जेएलएल इंडिया ने अपनी रिपोर्ट 'एचवीएसी हस्तक्षेपों के माध्यम से एक स्थायी दृष्टिकोण' में कहा कि एक कुशल एचवीएसी प्रणाली की मदद से वाणिज्यिक भवनों की ऊर्जा जरूरतों को कम किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, "केंद्रीकृत एचवीएसी प्रणाली वाले छह करोड़ वर्ग फुट कार्यालय स्थान में केवल 3.3 करोड़ वर्ग फुट में पानी आधारित वातानुकूलन का इस्तेमाल किया जाता है, जो हवा आधारित वातानुकूलन की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल है।" जेएलएल इंडिया ने एक बयान में कहा कि पानी आधारित वातानुकूलन प्रणाली के इस्तेमाल से मुंबई के प्रमुख कार्यालय भवनों में हर साल 18.5 करोड़ किलोवॉट ऊर्जा को बचाया जा सकता है, जिससे 1.48 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। इससे सालाना बिजली के बिल में 175 करोड़ रुपये की कमी आएगी।

इस्पात विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत आवेदन करने की समयसीमा 31 मई तक बढ़ी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने विशेष प्रकार के इस्पात के घरेलू विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहत योजना (पीएलआई) के तहत आवेदन देने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मई, 2022 कर दी है। एक आधिकारिक अधिसूचना से यह जानकारी मिली है। आवेदन की समयसीमा दूसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले इस्पात विनिर्माताओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मार्च थी, जिसे उस समय बढ़ाकर 30 अप्रैल किया गया था। इस्पात मंत्रालय की तरफ से 28 अप्रैल को जारी अधिसूचना में कहा गया, "इस्पात विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत आवेदन अब 31 मई, 2022 तक किया जा सकता है।" इससे पहले, मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया था कि सरकार इस्पात विनिर्माताओं की कुछ चिंताओं के बाद विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना में संशोधन पर विचार कर रही है। अधिकारी ने कहा था कि सरकार विशेष इस्पात के उत्पादन के लिए एक समान प्रोत्साहन देने की योजना पर काम करने के साथ इसमें अधिक ग्रेड शामिल करने पर विचार कर रही है....विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले सामान के लिए।

ड्यूरोफ्लेक्स ने अपने इंदौर संयंत्र में मैट्रेस का उत्पादन बढ़ाया

लॉन्ग ब्लॉक की सुविधा को जोड़ा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के अग्रणी स्लीप सॉल्यूशंस ब्राण्ड ड्यूरोफ्लेक्स ने हाल ही में इंदौर में अपने विशाल और अत्याधुनिक फोम एवं मैट्रेस विनिर्माण संयंत्र में लॉन्ग ब्लॉक की सुविधा जोड़ी है। हेनेनके जैसे वैश्विक अग्रणियों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोमिंग टेक्नोलॉजी से युक्त यह संयंत्र फोम हैण्डलिंग, फोम क्युरिंग, परिवहन एवं स्टोरेज समाधानों के ऑटोमेशन को संयंत्र के भीतर मजबूती और गति देने के लिये ड्यूरोफ्लेक्स की एक कोशिश है। इस नई सुविधा से संयंत्र की मैट्रेस (गद्दा) उत्पादन क्षमता तीन गुना बढ़ गई है और फोम के उत्पादन की क्षमता 4 गुना बढ़ गई है। नई सुविधा के बारे में ड्यूरोफ्लेक्स के सीईओ मोहनराज जे. ने कहा, बतौर एक ब्राण्ड, ड्यूरोफ्लेक्स का विजन पूरे देश में अपने उपभोक्ताओं को स्वस्थ) नींद देने में मदद करना है। हमने इस संयंत्र का अधिग्रहण 2020 में किया था, जब महामारी ने स्वास्थ्य और साफ-सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ाई थी और उपभोक्ता भरोसेमंद ब्राण्ड्स से अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद चाहते थे और इस प्रकार उद्योग में ब्राण्डेड चीजों का उपभोग बढ़ा। हमारे ब्राण्ड ने तब से देशभर में अपनी वृद्धि को दोगुना किया है और यह कदम राष्ट्रीय स्तर का स्लीप एंड होम सॉल्यूशंस ब्राण्ड बनने की दिशा में है। ड्यूरोफ्लेक्स बेहतर नींद लेने में भारत की मदद करने का अग्रणी दृष्टिकोण रखता है। ऑटोमैटिक ब्लॉक हैण्डलिंग सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जैसी नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को उच्च प्रदर्शन के स्त्र पर पहुँचाया है और विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानकों से क्षमता और लोचशीलता बढ़ाई है। इसका लक्ष्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसाय परिचालन का विस्तार करना है। यह संयंत्र अपनी सिग्नैचर रेंज ड्यूरोपेडिक (डॉक्टर द्वारा अनुशंसित भारत का पहला ऑर्थोपीडिक मैट्रेस) समेत मैट्रेसेस और स्लीप एसेसरीज की व्यारक श्रृंखला के उत्पादन के अलावा, ब्राण्ड के लगातार बढ़ रहे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के विनिर्माण को भी सहयोग देता है। इसमें घर से काम करने के लिये फर्नीचर, डिजाइनर बेड्स, और बहुत कुछ शामिल हैं। इंदौर शहर आज देश के सबसे तेजी से बढ़ रहे शहरों में से एक है और यह एक बाजार के तौर पर लाभकारी एवं विविधतापूर्ण अवसर देता है। यह शहर आने वाले समय में फर्नीचर का केन्द्र बनेगा और यह रणनीतिक रूप से स्थित है, जहाँ से ब्राण्ड उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के बाजारों में 24 घंटे के भीतर तेज गति से सेवा प्रदान कर सकता है।

केवल 90 दिनों में 20 लाख से ज्यादा इंटरव्यू के साथ मध्यप्रदेश दोबारा काम पर लौटा अपना डॉट को

भोपाल । आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे बड़े नौकरी और प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म apna.co , के अनुसार मध्यप्रदेश में लाखों पेशेवरों के लिए पिछले तीन महीने बहुत ही रोमांचक रहे हैं क्योंकि कोविड के कारण लगे लॉकडाउन के बाद अब बाजार दोबारा खुलने लगा है और ज़िंदगी दोबारा सामान्य हो रही है। राज्य में लगभग 10 लाख रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स के साथ, 'अपना' ने पिछले 90 दिनों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन से 20 लाख से अधिक इंटरव्यू करवाए हैं। मध्यप्रदेश भारत में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र बन गया है, जो विभिन्न इंडस्ट्री और सेक्टर्स में रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध करा रहा है। पिछले 90 दिनों में मप्र में सबसे लोकप्रिय नौकरियां टेलीकॉलर, डिलीवरी पर्सन, बिजनेस डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव, रिटेल एक्ज़ीक्यूटिव बैक-ऑफ़िस स्टाफ, ड्राइवर, डेटा एंट्री और सेल्स - फील्डवर्क रही हैं। महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के संकेत के रूप में apna.co ने इस दौरान 17 लाख से ज्यादा के अवसर दर्ज किए। 'अपना' के मध्यप्रदेश के आंकड़ों के अनुसार, इसके अधिकांश यूज़र्स भोपाल से बाहर हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा इंटरव्यू किए गए थे, जिससे यह मध्यभारत में नौकरी करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर बन गया है। उज्जैन में सबसे लोकप्रिय नौकरी डिलीवरी पर्सन की थी जबकि जबलपुर और उज्जैन में यूज़र्स टेलीकॉलर / बीपीओ की नौकरी के लिए आवेदन भेज रहे थे।

इस महीने की शुरुआत में सीएमआईई द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में मध्यप्रदेश को उन राज्यों में शामिल किया गया है, जहां बेरोजगारी दर कम है। इस रिपोर्ट में भारतीय राज्यों में बेरोजगारी की मैपिंग की गई है। रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में बेरोजगारी की दर 1.4ज्ञ है, जो भारत में अधिकांश राज्यों की बेरोजगारी की दर की तुलना में बहुत कम है। इस दर को और कम करने के लिए, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करके मध्यप्रदेश में प्रोफेशनल्स की मदद करना जरुरी है। मध्यप्रदेश के सभी यूज़र्स में से 30 प्रतिशत महिलाएं हैं और प्लेटफार्म ने राज्य में महिला प्रोफेशनल्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। मध्यप्रदेश में ज्यादातर महिलाओं ने टेलीकॉलर, डेटा एंट्री और रिसेप्शनिस्ट/फ्रंट ऑफिस जैसी नौकरियों के लिए आवेदन किया था। मध्यप्रदेश में 12वीं या उससे कम शैक्षणिक योग्यता वाले 'अपना' यूज़र्स में से लगभग 50 प्रतिशत को मोबाइल ऐप के जरिए रोजगार के सार्थक अवसर मिले हैं। अब, 'अपना' उनके सभी करियर विकल्पों के लिए एक डिफ़ॉल्ट प्लेटफॉर्म बन गया है।

कोरोना वैक्सीनेशनः बूस्टर डोज लेने का अंतराल घटा सकती है सरकार, विदेश यात्रा करने वाले लोगों को होगा फायदा

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में चौथी लहर की आशंका के बीच कोरोना वैक्सीन की तीसरी यानी बूस्टर डोज लेने का गैप कम किया जा सकता है। बुधवार को इस पर सरकार की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो सकती है। अभी फिलहाल बूस्टर डोज़ सिर्फ उन्हें दिए जा रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज नौ महीने पहले ली थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस गैप को घटाकर छह महीने किए जाने पर विचार किया जा सकता है। अमर उजाला को मिली जानकारी के अनुसार, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन उस डाटा पर चर्चा कर सकती है, जिसमें बताया गया है कि आखिर गैप कम करने से क्या फायदे होंगे। एनटीएजीआई के सदस्य इस डाटा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरी डोज़ लेने के बाद कब तक लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए इम्यूनिटी बनी रहती है।

मंत्रालय के एक सूत्र ने चर्चा में बताया कि इस वक्त अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों से कई देश बूस्टर डोज के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। परेशान लोग इसे लेकर लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ संबंधित मंत्रालयों से भी संपर्क कर रहे हैं। भारत में नौ महीने का गैप होने के चलते लोग बूस्टर डोज नहीं ले पा रहे हैं। कई देशों ने तीसरी डोज को लेकर गैप कम कर रखा है। ऐसे में सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर कोई निर्णय ले सकती है। पिछले दिनों ही मीडिया से चर्चा में नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोरोनावायरस और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयादेवन ने कहा था कि वैक्सीन के दूसरे डोज और बूस्टर डोज के बीच लंबे गैप से संक्रमण और बीमारी की गंभीरता से लड़ने में कमी आती है। उन्होंने अपनी स्टडी का हवाला देते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वैक्सीन की सेकंड डोज लेने के छह महीने बाद बूस्टर डोज लेता है तो वायरस के संक्रमण और उसकी गंभीरता से जुड़े मामलों में कमी आ जाती है। भारत में बूस्टर डोज़ को प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया गया है। देश में इस वक्त कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तीसरी डोज़ लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इन दोनों वैक्सीन से वायरस से लड़ने की क्षमता करीब आठ महीने तक रहती है। भारत में बूस्टर डोज पहले सिर्फ हेल्थ और फ्रंटलाइन स्टाफ को लगाई गई थी। इसके अलावा बुजुर्गों को भी इस लिस्ट में जोड़ा गया था। बाद में 10 अप्रैल को सरकार ने सभी के लिए बूस्टर डोज का एलान किया। सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, और आपने वैक्सीन की दूसरी डोज नौ महीने पहले या फिर 39 हफ्ते पहले लगवाई है तो आप तीसरी खुराक ले सकते हैं।

प्लास्टइण्डिया फाउण्डेशन ने इंटरनेशनल प्लास्टिक एक्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस एवं कन्वेंशन-प्लास्टइण्डिया 2023 के 11वें संस्करण की घोषणा की

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख भाई एल. मण्डाविया ने किया 'प्लास्टइण्डिया- 2023 के लोगो का अनावरण

प्लास्टइण्डिया-2023 भारत को विश्वस्तर पर प्लास्टिक के लिए सोर्सिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में करेगा काम

नई दिल्ली। प्लास्टइण्डिया फाउण्डेशन ने आज इंटरनेशनल प्लास्टिक एक्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस एवं कन्वेंशन के 11वें संस्करण 'प्लास्टइण्डिया-2023' की घोषणा की। प्लास्टइण्डिया 2023 का आयोजन आगामी 01 से 05 फरवरी 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली के नवनिर्मित अत्याधुनिक इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर में किया जायेगा। प्लास्टइण्डिया 2023 आधुनिक तकनीकों का सुविधाजन बनाने के साथ नवाचार स्थायित्वता एवं विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा, जो एक स्वच्छ वातावरण बनायें रखने में मदद के साथ स्थायी आर्थिक विकास की ओर ले जायेगा।

माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक, श्री मनसुख भाई एल मंडावियाजी ने राजधानी में एक कार्यक्रम में प्लास्टइण्डिया 2023 के लोगो, ब्रोशर और लक्ष्यों का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री भगवंतभाई खुबाजी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, (सी एंड एफ और एमएनआरई) और श्रीमती आरती आहूजाजी, आईएएस, भारत सरकार के सचिव (डीसीपीसी) भी उपस्थित थीं। प्लास्टइंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री जिगीश दोशी, राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री अशोक गोयल और एनईसी प्लास्टइंडिया 2023 के अध्यक्ष श्री अजय शाह भी उपस्थित थे।

विगत तीन दशकों में उत्पादन और खपत में कई गुना वृद्धि के साथ भारतीय प्लास्टिक उद्योग तेजी के साथ बढ़ रहा है। आज, भारत में प्लास्टिक निकायों का एक प्रमुख उद्देश्य निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देना और भारत को प्लास्टिक के उच्चतम उत्पादकों में से एक बनाना है। वर्तमान कारोबारी माहौल, भारत सरकार के आत्म निर्भर मूमेंट और वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के कारण से मजबूत हुआ है और यह प्लास्टिक उद्योग को बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है और उत्कृष्ट निर्यात अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2019-20 में प्लास्टिक का भारतीय निर्यात 10.00 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसके वर्ष 2025 तक 25.00 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

इस अवसर पर प्लास्टइण्डिया फाउण्डेशन के अध्यक्ष श्री जिगीश दोशी ने कहा, भारत दुनिया का प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेन्टर बनने की ओर अग्रसर है। इस उद्योग जिसमें लगभग 4 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 50,000 से अधिक प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं, वर्ष 2025 तक 9.1 लाख करोड़ (102 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंचने की उम्मीद है। हम विकास को सुविधाजनक बनाने और काम करने के लिए सरकार और उद्योग के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इन वर्षों में, प्लास्टिक उद्योग ने उन्नत इनोवेशन्स के साथ खुद को फिर से विकसित किया है और पर्यावरण के अनुकूल प्रसंस्करण और उपयोग तकनीकों को विकसित किया है जो पर्यावरण को प्रभावित नहीं करते हैं। प्लास्टइंडिया 2023 के लॉन्च के साथ, फाउंडेशन ने प्लास्टिक उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 10 लक्ष्यों को भी साझा किया है।

इस अवसर पर प्लास्टइंडिया 2023 नेशनल एक्जीक्यूटिव कौंसिल के अध्यक्ष श्री अजय शाह ने कहा, "भारतीय प्लास्टिक उद्योग प्रसंस्करण मशीनरी, उपकरण, और प्लास्टिक उत्पाद आपूर्तिकर्ताओं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण उपकरण के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और नए युग के क्षेत्रों के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रस्तुत करता है। हमारा उद्देश्य विश्व स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन करके भारतीय प्लास्टिक उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है ताकि ब्राण्ड नए उत्पादों को लॉन्च कर सकें, अपने नेटवर्क को विकसित कर सकें, नई तकनीकों को सीख सकें और वैश्विक स्तर पर विचारों का आदान-प्रदान कर सकें।" श्री शाह ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा "प्लास्टइंडिया 2023" का उद्देश्य न केवल प्लास्टिक उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शकों और आगंतुकों को एक साथ लाना है, बल्कि उद्योग में नई तकनीकों और नवाचारों को प्रदर्शित करना भी है। यह नए उत्पादों को प्रदर्शित करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निर्णय निर्माताओं से जुड़ने का एक शानदार अवसर है। 11वीं प्लास्टइंडिया प्रदर्शनी 1 से 5 फरवरी 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली, के नवनिर्मित अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र में आयोजित की जाएगी। यह प्रदर्शनी प्रदर्शकों को प्रोसेसिंग, मशीनरी में अपने नए इनोवेशन्स को प्रदर्शित करने, मोल्ड्स एण्ड डाइस, सहायक उपकरण, प्रिंटिंग और पैकेजिंग, कच्चा माल सहित बहुत कुछ प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगी।

यह लक्ष्य इस प्रकार हैं

- भारत को प्लास्टिक निर्माण के लिए नम्बर वन डेस्टिनेशन बनाना
- भारतीय प्लास्टिक उद्योग के विकास को सुगम बनाना
- देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना
- भारत को प्लास्टिक के लिए वैश्विक सोर्सिंग हब बनाने पर जोर देना
- ताजा नवीन तकनीकों को प्रोत्साहित करना
- भारतीय प्लास्टिक उद्योग के लिए तकनीकी रूप से कुशल जनशक्ति बढ़ाने के लिए
- प्लास्टिक का निर्यात बढ़ाने के लिए
- प्लास्टिक उद्योग की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि
- अवसरों को प्रदर्शित करते हुए, वैश्विक संस्थाएं टैप कर सकती हैं
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक के उपयोग से जुड़े क्षेत्रों के विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करें

मध्य प्रदेश सरकार 450 करोड़ रुपये की लागत से इंदौर में बनाएगी स्टार्टअप पार्क

इंदौर। एजेंसी

मध्य प्रदेश सरकार सूबे की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में युवा उद्यमियों के नये कारोबारी उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पार्क बनाएगी। इसके पहले चरण के निर्माण में करीब 450 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। आईडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विवेक श्रोत्रिय ने बताया,"हमने शहर के सुपर कॉरिडोर की 20 एकड़ जमीन पर स्टार्टअप पार्क बनाने के लिए वास्तुविद सलाहकार और निर्माण योजना के लिए वैश्विक स्तर पर निविदाएं मंगाई हैं।" उन्होंने बताया कि स्टार्टअप पार्क परियोजना के पहले चरण में एक बहुमंजिला परिसर बनाया जाएगा जिसपर करीब 450 करोड़ रुपये की लागत आ सकती है। श्रोत्रिय ने बताया कि स्टार्टअप उद्यमियों से तय रकम लेकर उन्हें इस परिसर में पट्टे (लीज) पर जगह दी जाएगी। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार अपनी स्टार्टअप नीति 13 मई को इंदौर में पेश करने की योजना पर काम कर रही है। इंदौर से लोकसभा सदस्य शंकर लालवानी ने बताया,"हालांकि, अभी अंतिम कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रदेश की स्टार्टअप नीति पेश करने के लिए समय दें।" गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 29 अप्रैल को एक कार्यक्रम में कहा था कि प्रदेश सरकार मई में अपनी स्टार्टअप नीति पेश करेगी और इसके तहत युवा उद्यमियों की नवाचारी कारोबारी परियोजनाओं के लिए पूंजी की व्यवस्था भी की जाएगी। कारोबार जगत के जानकारों ने बताया कि इंदौर में फिलहाल करीब 450 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जबकि ऐसे 250 से ज्यादा नये उद्यम जल्द अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं।

भारत ने 2022 में श्रीलंका को दी तीन अरब डॉलर से अधिक की सहायता: भारतीय उच्चायोग

कोलंबो। एजेंसी

भारत ने कर्ज में डूबे श्रीलंका के लिये ऋण, कर्ज सुविधा और द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के तहत तीन अरब डॉलर से अधिक की सहायता उपलब्ध करायी है। भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भारत ने श्रीलंका के तेजी से घटे ईंधन भंडार को भरने के लिये सोमवार को 20 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त ऋण सुविधा दी है। श्रीलंका में मौजूदा संकट का एक बड़ा कारण विदेशी मुद्रा की कमी है। इसका मतलब है कि देश जरूरी सामान के आयात के लिये भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। इससे प्रमुख जिंसों की कमी होने के साथ दाम भी बढ़ रहे हैं। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा, "खाद्यान्न, दवाएं और अन्य जरूरी सामान खरीदने को लेकर एक अरब डॉलर की कर्ज सुविधा पहले से जारी है।" भारत ने 16,000 टन चावल की आपूर्ति की है। उसका वितरण किया जा रहा है। बयान के अनुसार चावल, औषधि और औद्योगिक कच्चे माल की अतिरिक्त खेप कर्ज सुविधा के अंतर्गत है। इसमें कहा गया है, "डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के लिये 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त कर्ज सुविधा से देश को विभिन्न ईंधन प्राप्त करने में मदद मिली है...।" उच्चायोग के बयान के अनुसार, कुल मिलाकर श्रीलंका को 2022 में तीन अरब डॉलर की सहायता दी जा चुकी है। इसमें एक अरब डॉलर की कर्ज सुविधा जरूरी सामान खरीदने को लेकर, 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने तथा 40 करोड़ डॉलर की द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली सुविधा शामिल है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें स्थान से फिसल कर 150वें स्थान पर पहुंचा

नयी दिल्ली। एजेंसी

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। एक वैश्विक मीडिया निगरानीकर्ता द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (आरएसएफ) द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है, जिसमें पाकिस्तान 157वें, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह रैंकिंग कुल 180 देशों की है। आरएसएफ 2022 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार, नेपाल वैश्विक रैंकिंग में 76वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि पिछले साल, उसे 106वें, पाकिस्तान को 145वें, श्रीलंका को 127वें, बांग्लादेश को 152वें और म्यांमार को 140वें स्थान पर रखा गया था। इस साल नॉर्वे (प्रथम) डेनमार्क (दूसरे), स्वीडन (तीसरे) एस्टोनिया (चौथे) और फिनलैंड (पांचवें) स्थान पर है, जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों और क्षेत्रों की सूची में सबसे नीचे है। रूस को इस रिपोर्ट में 155वें स्थान पर रखा गया है, जो पिछले साल 150वें स्थान से नीचे था, जबकि चीन दो पायदान ऊपर चढ़ते हुए 175वें स्थान पर आ गया। पिछले साल चीन 177वें स्थान पर था। अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा, ''विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और नौ अन्य मानवाधिकार संगठन भारतीय अधिकारियों से पत्रकारों और ऑनलाइन आलोचकों को उनके काम के लिए निशाना बनाना बंद करने का आग्रह करते हैं।'' बयान में आगे कहा गया कि '' विशेष रूप से, आतंकवाद और देशद्रोह कानूनों के तहत उन पर मुकदमा चलाना बंद कर देना चाहिए।'' रिपोर्टर्स सेन्स फ्रंटियर्स (आरएसएफ) ने कहा कि ''भारतीय अधिकारियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए, राजनीति से प्रेरित आरोपों में हिरासत में लिए गए किसी भी पत्रकार को रिहा कर देना चाहिए और उन्हें निशाना बनाना तथा स्वतंत्र मीडिया का गला घोंटना बंद करना चाहिए।'' इसने कहा, ''अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को निशाना बनाने के साथ-साथ असहमति पर व्यापक कार्रवाई ने हिंदू राष्ट्रवादियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से भारत सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को धमकाने, परेशान करने और दुर्व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया है।'' आरएसएफ 2022 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत के तीन पत्रकार संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा, '' नौकरी की असुरक्षा बढ़ी हैं, वहीं प्रेस की स्वतंत्रता पर हमलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। भारत ने इस संबंध में रैंकिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इंडियन वुमंस प्रेस क्लब, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और प्रेस एसोसिएशन ने कहा, ''पत्रकारों को मामूली कारणों से कठोर कानूनों के तहत कैद किया गया है और कुछ मौकों पर सोशल मीडिया मंच पर मौजूद कानून के स्वयंभू संरक्षकों से उन्हें जान को खतरे का सामना करना पड़ा है।''

कोरोना वायरस टीकाकरणः 5-12 साल के बच्चों को जल्द लग सकती है वैक्सीन, तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली। देश में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों को दी जाने वाली कोरोना वायरस वैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही पांच से 12 वर्ष तक के बच्चों को भी टीका देने का रास्ता साफ हो सकता है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) पांच से 12 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके कोवोवैक्स और कॉर्बेवैक्स के डाटा की समीक्षा करने जा रहा है। अगर एनटीएजीआई को डाटा संतोषजनक लगता है तो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान से कम उम्र के बच्चों को जोड़ने का रास्ता तैयार हो सकता है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख भाई मंडाविया ने भी कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर पांच से 12 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण पर कोई फैसला लिया जाएगा।

टीकाकरण अभियान से जोड़ने की कोई योजना नहीं

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कहा कि अभी फिलहाल 12 साल से कम उम्र के बच्चों को टीकाकरण अभियान से जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं है। हालांकि अब काफी कुछ एनटीएजीआई की आगामी समीक्षा बैठक पर निर्भर करता है। पिछले हफ्ते एनटीएजीआई की स्थाई तकनीकी उप-समिति ने 12-17 साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के कोवोवैक्स को राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम से जोड़ने की सिफारिश की थी। फिलहाल विशेषज्ञ समिति 5-12 साल के बच्चों के लिए टीका निर्माताओं द्वारा दिए गए डाटा की समीक्षा कर रही है। इस समीक्षा के आधार पर कोई निर्णय लिया जाएगा। पिछले हफ्ते भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने 5-12 साल के बच्चों को कॉर्बेवैक्स (बायोलॉजिकल ई) और कोवॉक्सिन (भारत बायोटेक) के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी, जबकि जायडस लाइफसाइंसेज के जायकोव-डी को 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई थी। भारत ने अब तक 12-14 साल के उम्र समूह के 2.91 करोड़ बच्चों को और 15-17 साल उम्र वर्ग के 10.1 करोड़ बच्चों को टीके दिए हैं।

अभिभावकों में बढ़ रही है चिंता

इधर देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसी बीच कई राज्यों में बच्चों के स्कूल भी शुरू हो गए है। ऐसे में अभिभावकों को टीके को लेकर चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते कहा था कि सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण सरकार के लिए प्राथमिकता है और स्कूलों में विशेष तरह के कार्यक्रम आयोजित कराना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि हमारी प्राथमिकता सभी पात्र बच्चों को जल्द से जल्द टीके लगवाना है। स्कूलों में विशेष अभियान की जरूरत होगी। शिक्षकों और अभिभावकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए।'

इस बीच डॉक्टरों का भी कहना है कि छोटे बच्चों का टीकाकरण जरूरी है। अमर उजाला से चर्चा में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में कोविड-19 का संक्रमण तुलनात्मक रूप से ज्यादा गंभीर नहीं रहा है, लेकिन हमने पाया कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों में दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 के मामले पाए गए। छोटे बच्चों में कोविड-19 संक्रमण को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। 5-12 साल के उम्र वर्ग में कई मौत और गंभीर मामलों को देखते हुए कई देशों ने इस समूह को टीके देने की शुरुआत की है।

इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के विशेषज्ञ समूह ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोविड-19 टीके देने की सिफारिश की है। कॉर्बेवैक्स एक प्रोटीन सब-यूनिट टीका है, जिसे एक स्थापित मंच का इस्तेमाल कर बनाया जाता है, जो हेपेटाइटिस-बी की तरह ही है। हेपेटाइटिस-बी टीका पांच साल और इससे अधिक उम्र समूह के लिए है, जबकि कोवैक्सीन छह साल और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए निष्क्रिय टीका है। दोनों ही टीके बच्चों में इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों में कोविड-19 के कई मामले की वजह से संक्रमण का केंद्र तैयार हुई है और कई राज्यों में हाल में स्कूल बंद भी हुए हैं।

सिलेक्टेड होम्म ने अपना नया स्टोर लॉन्च किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

प्रीमियम यूरोपीय मेन्सवियर ब्रांड सिलेक्टेड होम्म ने फोर्ट मुंबई में एक प्रतिष्ठित हब ब्रैडी हाउस में अपना नया स्टोर लॉन्च किया है इस सिलेक्टेड स्टोर में क्रिस्प इंटीरियर विशिष्ट डेकोर और समय के प्रभावों से मुक्त मेन्सवियर क्लासिक्स का शानदार प्रदर्शन किया गया है इस बेहतरीन मेन्सवियर को खास लोगों की खास पसंद को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है इस महत्वपूर्ण स्टोर का ब्रांड एंबेसडर सैफ अली खान ने स्टोर का उद्घाटन किया और लोगों को सिलेक्टेड होम्म के नए कलेक्शन की एक झलक भी दिखाई। इस नए स्टोर के लॉन्च पर बात करते हुए बोलते हुए विनीत गौतम सीईओ एंड कंट्री हेड बेस्टसेलर इंडिया ने कहा कि हम मुंबई में ब्रैडी हाउस जैसी हेरीटेज बिल्डिंग में सिलेक्टेड होम्म के लिए एक नई डेस्टिनेशन खोजने को लेकर बेहद उत्साहित हैं इसके अलावा हमारे ब्रांड एंबेसडर की तुलना में इस लॉन्च का उत्सव मनाने से बेहतर क्या हो सकता है सैफ अली खान जो पूरी तरह से क्लासिक भव्य और पूरी तरह से स्टाइलिश होने की साथ ही सिलेक्टेड होम्म की सही भावना का प्रतीक हैं हम इस तरह के कई और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हैं। इस मौके पर प्रतिक्रिया देते हुए सिलेक्टेड होम्म के ब्रांड एंबेसडर सैफ अली खान ने कहा कि मैं लंबे समय से सिलेक्टेड होम्म को समर्पित रहा हूं इसलिए मुझे ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने में वास्तव में खुशी हो रही है सिलेक्टेड होम्म आज के आधुनिक व्यक्ति का आदर्श उदाहरण है जो कि आत्मविश्वासी प्रामाणिक और स्वीकार्य है ब्रांड मेरे व्यक्तिगत विश्वासों का विस्तार है और इसलिए इस ऑल न्यू ब्रैडी हाउस स्टोर के लॉन्च का जश्न मनाते हुए मुझे खुशी हो रही है, वह भी पिछले कुछ वर्षों के बाद व्यक्तिगत रूप से लॉन्च करते हुए और भी खास लग रहा है। स्टोर पर पूरी तरह से नई कलेक्शन दिखने की एक सीरीज प्रदान करता है जो हर अवसर के लिए बिल्कुल सही होता है रेंज प्रगतिशील विवरण के साथ बहुमुखी प्रतिभा और बढिया सिलाई प्रदर्शित करती है ब्रांड ऑफर में वर्क-स्टेपल होना चाहिए जो काम से अवकाश तक निर्बाध रूप से परिवर्तित हो एक क्रिस्प सफेद शर्ट से लेकर सब कुछ मिल सकता है जो हर आदमी की अलमारी में अलग-अलग रंगों में अच्छी तरह से फिट ट्राउजर के लिए मेन बेस है। बेस्पोक ब्लेजर और सूट जो आंखों पर आसान होते हैं, एक रिफाइंड लेकिन अंडरस्टेटेड लुक प्रदान करते हैं। ब्रांड शर्ट, ब्लेज, जींस, टी-शर्ट, चिनोस, टेलरिंग और बहुत कुछ का क्यूरेटेड सिलेक्शन प्रदर्शित करता है।

News यू केन USE

सी-डॉट, सी-डैक के बीच आपसी सहयोग का करार

नयी दिल्ली। एजेंसी

दूरसंचार और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों सी-डॉट और सी-डैक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वदेशी स्तर पर तकनीकी डिजाइन एवं विकास को बढ़ावा देने के इरादे से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 'सेमीकॉन इंडिया 2022' सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

सोमवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक दूरसंचार मंत्रालय के अग्रणी शोध एवं विकास संगठन सी-डॉट और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय का स्वायत्त संगठन सी-डैक मिलकर दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करेंगे। विज्ञप्ति के मुताबिक, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) एक-दूसरे को उसके विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद पहुंचाने के लिए काम करेंगे। इस करार के तहत दोनों ही संगठन 4जी एवं 5जी तकनीक, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), मशीन लर्निंग, पैकेट कोर और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे।

ड्रोन तकनीक को किसानों तक ले जाने के लिए परिस्थितियां अनुकूलः तोमर

नयी दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि वह 'किसान ड्रोन' के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है और मौजूदा परिस्थितियां इस तकनीक को किसानों तक ले जाने के लिए अनुकूल हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण सरकार की कार्यसूची में है। उन्होंने कहा कि फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन' को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। तोमर ने कहा कि किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ड्रोन खरीदने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा कि अन्य किसानों को यह ड्रोन खरीदने के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम चार लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

भारत, जर्मनी का हरित हाइड्रोजन कार्यबल पर समझौता

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत और जर्मनी ने सोमवार को हरित हाइड्रोजन पर कार्यबल बनाने की सहमति जताई। दोनों देशों ने इस बारे में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।

केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और जर्मनी के आर्थिक मामलों एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने वर्चुअल तरीके से इस संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सिंह ने कहा कि भारत ऊर्जा बदलाव में वैश्विक स्तर पर अगुवा के रूप में उभरा है। दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि में भारत सबसे आगे है।

परदेस में चाकरी, सामाजिक सम्मान और देशप्रेम

राजकुमार जैन
स्वतंत्र विचारक

हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है बेहतर मानव संसाधनों की कमी, हमें शिकायत रहती है कि हमारे देश में बेहतर वैज्ञानिक नहीं हैं, हमारे पास बेहतर प्रबंधक नहीं हैं, हमारे नीति निर्धारक दोयम दर्जे के है, हमारे डॉक्टर सबसे अच्छे नहीं हैं, हमारे शैक्षणिक सांस्थान उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षक विहीन है आदि आदि, हम यह मानते हैं कि विदेशों में सब कुछ अच्छा है और हमेशा से हम इन कमियों का उत्तरदायित्व सरकार की रीति नीति को समझते आ रहे है, हम यह मानते है कि जिस देश में हम पैदा हए है, जिस देश ने हमें पाल पोसकर बड़ा किया, और एक हद तक शिक्षित बनाया उसी मातृभूमि की जब सेवा करने का अवसर आता है तब हमें हमारे अपने वतन में अपने लिए बेहतर अवसर नहीं दिखाई पड़ते हैं और देश को कुछ देने की बजाय हम यह कहकर विदेश जाना पसंद करते है कि मेरा देश मुझे क्या दे रहा है ?

अगर इस विषय पर ईमानदारी सहित गम्भीरता से इसकी तह तक जाकर समझा जाए तो वस्तुतःबेहतर मानव संसाधन की इस कमी की जिम्मेदारी हमारे अपने ही परिवारों पर आती है और यह एक बाहरी नहीं हमारी अपनी आंतरिक समस्या है, आइए समझते हैं ऐसा क्यों है... हम हमेशा से यही चाहते आये है कि हमारा मेधावी, बुद्धिमान और कुशाग्र बच्चा आगे पढ़ने या पढाई के बाद नौकरी करने विदेश जाए और सम्भव हो तो विश्व के सबसे समृद्ध देश मे बस जाय । हमारी नजर में सफल कहलाने के लिए यही एक बेहतर कैरियर ऑप्शन है, और तो और हम इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा अपने परिवार से बिछुड़ कर, अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश में है और इस कृत्य के लिए हम समाज में सम्मान भी पाते हैं। अब दूसरे देशों के हालात देखते है आपने कभी सुना कि जापानी वर्क फोर्स या केनेडियन लेबर या नार्वेजियन विशेषज्ञ या चीनी इंजीनियर या जर्मन वैज्ञानिक या अमरीकी डॉक्टर किसी और देश में जाकर उस देश की तरक्की में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा रहे हैं..... नहीं सुना ना, क्योंकि वहां देशप्रेम की भावना घर के अंदर से ही उपजती है, वहां देश को अपनी निजी सफलता से ऊपर माना जाता है, वहां के समाज में विदेश में जाकर विदेशियों के लिए काम करने को सम्मान की नजर से नही देखा जाता। हम भारतीय हर समस्या के लिए सिर्फ सरकार को दोष देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, क्या हमने कभी यह सोचा कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को अच्छे इंसान या बेहतरीन नागरिक बना रहे हैं (उस किस्म के गुणवान मानव जिनकी अपेक्षा हम दूसरों से करते है) जवाब है एक बड़ा नहीं बल्कि हम भारतीय अपने बच्चों को संस्कारों की बजाय भौतिक सुविधा और धन अर्जन को प्राथमिकता देने की शिक्षा देते हैं । हम अपनी आने वाली पीढी के मन में देशप्रेम का जज्बा भरने में पूर्णतया नाकाम रहे है, शायद नाकाम सही शब्द नहीं है, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं और हम अपने बच्चों में देशप्रेम या देशभक्ति भरने का कोई प्रयास तक नही करते तो नाकाम कैसे हए ।

अब जब आप और हम स्वयम आगे बढ़कर और कई मामलों में बच्चों की अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर सिर्फ भौतिक सुविधाओं और धन के लालच में हमारी बेहतरीन सन्तानों (जो देश को बदल सकते हैं) को विदेशियों की सेवा चाकरी करने भेज रहें है तो फिर इन बची हुई कम योग्य सन्तानों द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणाम (जिसमे अधिकारी, कर्मचारी, नेता, व्यवसायी सभी शामिल) को बुरा भला कहने से क्या हासिल होगा । वो अंग्रेजी में कहते हैं ना what we get is what we deserve.

आप अच्छे परिणाम देने की उम्मीद किनसे कर रहे है वो लोग जो अपेक्षित रूप से सक्षम या उतने बुद्धिमान है ही नही, वो तो वही दे पाएंगे ना जो उन्हें आता है, जो संस्कार हमारे परिवारों ने अपनी संतानों को दिए है वो वैसा ही व्यवहार करेंगे । देखा जाय तो ये लोग जिनको गाहे बगाहे गरियाना हमारा प्रिय राष्ट्रीय शगल है वो भी हमारे अपने ही लोग हैं, ये हमारे गैर पसंदीदा अक्षम या भृष्ट लोग किसी दूसरे देश या ग्रह से तो अवतरित नहीं हए है, इनको परिवार से और समाज से जो शिक्षा मिली वही वो अब वापस लौटा रहे हैं ।

अपनी मेधावी संतानों को अपने ही देश में रहकर देश के विकास में योगदान देने को प्रेरित करने की संस्कृति अपनाए बगैर इस देश में वो बदलाव नही आ पायेगा जिसकी हम निरन्तर कल्पना करते रहते है। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हमारा देश ऐसे ही चलता रहेगा और हम अपनी ही पैदा की हुई स्थितियों से अपनी घनघोर नापसन्दगी जाहिर करते रहेंगे।

तो मुद्दे की बात यह है कि देश के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है परिवार, परिवार में सन्तान का लालन पालन जिस प्रकार हुआ है वैसे ही नागरिक हमें मिलते हैं, बात किसी एक परिवार की नहीं है इसे व्यापक रूप से देखना होगा, क्यों हमें ऐसे नागरिक मिल रहे हैं जिन्हें हम पसन्द नही करते, किसने पैदा किया इन्हें, किसने इन्हें पाला पोसा, किसने इन्हें बेईमान बनाया ? हमने ही ना ..... तो फिर कैसा शिकवा, किससे शिकायत, कौन दोषी ? जय जय

रिसर्च में हुआ खुलासा, हवा के जरिए भी कोरोना वायरस के कण फैला सकते हैं संक्रमण

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस (SARS-CoV-2) के प्रसार का सटीक तंत्र मायावी बना हुआ है। महामारी विज्ञानियों ने अब पाया है कि जिन देशों की आबादी ने महामारी के दौरान मास्क पहना था, वे कम प्रभावित हुए थे। हालांकि, अब कोविड के हवाई प्रसारण की संभावना की पुष्टि की गई है। हैदराबाद और मोहाली के अस्पतालों के साथ CSIR-CCMB, हैदराबाद और CSIR-IMTech, चंडीगढ़ के वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा किए गए एक सहयोगी अध्ययन ने SARS-CoV-2 के हवाई संचरण की पुष्टि की। यह अध्ययन अब जर्नल ऑफ एरोसोल साइंस में प्रकाशित हुआ है।

वैज्ञानिकों ने कोविड-19 रोगियों के कब्जे वाले विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए हवा के नमूनों से कोरोना वायरस जीनोम सामग्री का विश्लेषण किया। ये नमूने अस्पतालों, बंद कमरों और घर का क्वारंटाइन वाला कमरा था, जिनमें केवल कोविड-19 रोगियों ने एक छोटी अवधि बिताई थी। उन्होंने पाया कि कोविड-19 रोगियों के आसपास हवा में वायरस का अक्सर पता

लगाया जा सकता है और परिसर में मौजूद रोगियों की संख्या के साथ सकारात्मकता दर में वृद्धि हुई है। अध्ययन से यह भी पता चला कि वायरस आईसीयू के साथ-साथ अस्पतालों के गैर-आईसीयू वर्गों में मौजूद था, यह सुझाव देता है कि रोगियों ने संक्रमण की गंभीरता के बावजूद वायरस को हवा में छोड़ा।

अध्ययन में हवा में व्यवहार्य कोरोना वायरस पाया गया, जो जीवित कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है और ये लंबी दूरी तक फैल सकता है। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि संक्रमण के प्रसार से बचने के लिए मास्क पहनना जारी रखें। अध्ययन में शामिल वैज्ञानिक शिवरंजनी मोहरीर ने कहा, ''हमारे परिणामों से पता चला है कि बंद स्थानों में वेंटिलेशन के अभाव में कोरोना वायरस कुछ समय के लिए हवा में रह सकता है। हमने पाया कि हवा में वायरस होने की सकारात्मकता दर 75% थी जब दो या दो से अधिक कोविड-19 रोगी एक कमरे में मौजूद थे, जबकि 15.8% के विपरीत जब एक या कोई कोविड-19 रोगी कमरे में नहीं था।'' मोहरीर ने कहा, ''हमारे अवलोकन पिछले अध्ययनों के समवर्ती हैं जो बताते हैं कि SARS-CoV-2 RNA की सांद्रता बाहरी हवा की तुलना में इनडोर हवा में अधिक है। सामुदायिक इनडोर सेटिंग्स की तुलना में अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में एकाग्रता अधिक है, जहां बड़ी संख्या में कोविड रोगियों की मेजबानी होती है।'' अध्ययन के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ राकेश मिश्रा, सीसीएमबी में एसीएसआईआर प्रतिष्ठित एमेरिटस प्रोफेसर और टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के निदेशक ने कहा, ''जैसा कि हम इन-पर्सन गतिविधियों का संचालन करने के लिए वापस आ गए हैं, कक्षाओं और मीटिंग हॉल जैसे स्थानों की संक्रमण क्षमता की भविष्यवाणी करने के लिए हवाई निगरानी एक उपयोगी साधन है। यह संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए रणनीतियों को परिष्कृत करने में मदद कर सकता है।'' उन्होंने कहा कि हवाई निगरानी तकनीक केवल कोरोना वायरस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे अन्य हवाई संक्रमणों की निगरानी के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है।

रियलमी ने प्रस्तुत किया रियलमी जीटी नियो 3

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते हुए स्मार्टफोन ब्रांड, रियलमी ने एक बार फिर अपना लेटेस्ट रियलमी जीटी नियो 3 लॉन्च करके बाजार में हलचल मचा दी है। 150 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नॉलॉजी वाला यह दुनिया का पहला और सबसे तेजी से चार्ज होने वाला स्मार्टफोन है। इस अत्याधुनिक स्मार्टफोन के साथ, रियलमी ने अपने विस्तृत एआईओटी पोर्टफोलियो में तीन नए उत्पाद रियलमी पैड मिनी, रियलमी बड्स क्यू2एस और रियलमी स्मार्ट टीवी एक्स फुल एचडी प्रस्तुत किए हैं। इस लॉन्च के बारे में श्री माधव शेठ, सीईओ, रियलमी इंडिया, वीपी, रियलमी एवं प्रेसिडेंट, रियलमी इंटरनेशनल बिज़नेस ग्रुप ने कहा रियलमी को सदैव अपने ग्राहकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करने में खुशी मिली है। हमारा ब्रांड टेक उद्योग में इनोवेशन लेकर आता है और हम रियलमी जीटी नियो 3 के साथ 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग टेक्नॉलॉजी प्रस्तुत करके बहुत उत्साहित हैं। हमारी जीटी नियो 3 सीरीज़ हमारा स्पीड फ्लैगशिप है, और हमारी विशाल जीटी सीरीज़ का अंग है, जिसके द्वारा हम अपने प्रीमियम स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहे हैं। इस साल हम प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। हमें अभी तक अपने ग्राहकों से बहुत शानदार प्रतिक्रिया मिली है। हम जल्द ही चार साल पूरे करने वाले हैं और हमें अपने इस लंबे सफर पर गर्व है। हमारा उद्देश्य शुरुआत से ही अपने यूज़र्स को सर्वश्रेष्ठ टेक्नॉलॉजी एवं डिज़ाईन प्रदान करना है, जो हम आने वाले सालों में भी करते रहेंगे।''

माइक्रोटेक इंटरनेशनल ने वित्त वर्ष 2021-22 में नए वर्टिकल के साथ 26% की प्रगतिशील बढ़त हासिल की

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

माइक्रोटेक – भारत के सबसे भरोसे मंद ब्रांडों में से एक ने अपनी शानदार सफलता के साथ आगे बढ़ना जारी रखते हुए वित्त वर्ष 2021-2022 में 26३ की बढ़त दर्ज की। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 1700 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया। पिछले कुछ सालों की जबरदस्त कामयाबी के साथ-साथ अपनी उत्पाद श्रृंखलाओं के विस्तार पर भरोसा रखते हुए , माइक्रोटेक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 50३ से ज्यादा का विकास लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सुबोध गुप्ता, सीएमडी माइक्रोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने कहा, 'मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि महामारी से प्रेरित चुनौतियों के बावजूद, हमने अपने व्यापार का विस्तार किया है और अपने सभी कर्मचारियों का ध्यान रखा है जो हमारे संगठन का आधार बने हुए हैं। हम देश में नंबर एक यूपीएस और इन्वर्टर ब्रांड हैं। जबकि हम बाजार में अपनी स्थिति को और बढ़ाने के लिए इन श्रेणियों पर निर्माण करना जारी रखेंगे, हमारा ध्यान सौर, विद्युत और स्वास्थ्य से वासहित हमारी नई श्रेणियों पर होगा ताकि इन श्रेणियों में भी उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा किया जा सके' जबकि, पिछले दो सालों में दुनिया भर में सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और अन्य रुकावटों जैसे कई उपायों के कारण विनिर्माण और आपूर्ति-श्रृंखला गति विधियों में गंभीर बाधाओं के कारण दुनिया के लगभग हर उद्योग को झटका लगा है। तबभी, माइक्रोटेकने स्वास्थ्य सेवा और सौर ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखा है और भारत में अपने प्रभाव का विस्तार किया है और साथ ही 20३ देशों में एक निर्यात कभी है। कंपनी ने ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेब्युलाइज़र, थर्मामीटर आदि उत्पादों के उत्पादन के साथ भारत के बढ़ते स्वास्थ्य सेवा बाजार में प्रवेश किया। ऑक्सीजन कां सैंट्रेटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, इसने पिछले साल 'मेड इन इंडिया' ऑक्सीजन कांसैंट्रेटर का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। माइक्रोटेक ने पीएम केयर्स के तहत ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) को 7500 ऑक्सीजन कां सैंट्रेटर की आपूर्ति की है, जिससे 'मेक इन इंडिया' और 'आत्म निर्भर भारत' सहित भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहलों को और बढ़ावा मिला है।

16 मई को होगा चंद्र ग्रहण: भारत में नहीं दिखेगा चंद्र ग्रहण और इसका सूतक भी नहीं रहेगा, वैशाख पूर्णिमा पर करें दान-पुण्य

सोमवार, 16 मई 2022 को चंद्र ग्रहण होगा। इस दिन वैशाख मास की पूर्णिमा है। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इस कारण ग्रहण का सूतक नहीं रहेगा। वैशाख पूर्णिमा से संबंधित पूजन कर्म और अन्य सामान्य पूजा-पाठ के लिए कोई बाधा नहीं रहेगी। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा के मुताबिक भारतीय समयानुसार ग्रहण की शुरुआत सुबह 7.58 बजे होगी और ग्रहण 11.25 बजे खत्म होगा। यह ग्रहण कनाडा, न्यूजीलैंड के कुछ भागों में, जर्मनी में दिखेगा। 30 अप्रैल को वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण हुआ था, ये ग्रहण भी भारत में नहीं दिखा था। आचार्य वराहमिहिर की बृहत्संहिता में लिखा है कि जब एक ही माह में दो ग्रहण होते हैं तो सैन्य हलचल बढ़ती है और किसी देश में तख्तापलट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में हो रहा है। ग्रहण जहां दिखाई देगा, वहीं इसकी धार्मिक मान्यताएं मान्य होंगी। भारत में ग्रहण का कोई सूतक नहीं होगा और न ही भारत देश में रहने वाले वृश्चिक राशि के लोगों पर इस ग्रहण का कोई असर होगा।

वैशाख पूर्णिमा पर कर सकेंगे पुण्य कर्म

भारत में ग्रहण नहीं दिखने से यहां ग्रहण से संबंधित कोई नियम मान्य नहीं होगा। इस कारण वैशाख पूर्णिमा से संबंधित सभी पुण्य कर्मों में किसी तरह की कोई बाधा नहीं रहेगी। पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। किसी तीर्थ क्षेत्र के मंदिरों के दर्शन करें। दान-पुण्य करें।

पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा करने की परंपरा है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें। ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।

सोमवार को पूर्णिमा होने से इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध और फिर से जल चढ़ाकर अभिषेक करना चाहिए। धूप-दीप जलाएं। ऊँ नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें।

पैसों की तंगी दूर करते हैं ये 5 चमत्कारिक रत्न, धन-संपदा में होती है बरकत

हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि उसे पैसों की कभी दिक्कत न हो और मां लक्ष्मी का साथ हमेशा बना रहे। कई बार खूब मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं रुकता है और बेवजह धन खर्च होता रहता है। रत्न शास्त्र में धन या पैसों से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं। रत्न शास्त्र में कुछ ऐसे रत्नों का जिक्र है जिनको धारण करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। जानिए ऐसे रत्नों के बारे में-

1. सुनहला रत्न

रत्न शास्त्र के अनुसार, बेवजह धन हानि या आर्थिक नुकसान होने पर सुनहला रत्न धारण करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के दिन बदलने लगते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि अगर घर में धन टिक न रहा हो तो भी सुनहला रत्न धारण किया जा सकता है। कहते हैं कि इस रत्न से लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है।

2. हरे रंग का जेड स्टोन

अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं और आर्थिक रुप से मजबूती चाहते हैं तो हरे रंग का जेड स्टोन धारण करना उत्तम रहता है। कहा जाता है कि जेड स्टोन से व्यक्ति को उसके काम पर फोकस करने में मदद मिलती है और वह बिजनेस संबंधी सही फैसला लेता है। जेड स्टोन को धन-समृद्धि के लिए भी उत्तम माना जाता है।

3. टाइगर रत्न

रत्न शास्त्र में टाइगर रत्न को सबसे प्रभावी और शीघ्र फलदायी वाला रत्न बताया गया है। कहा जाता है कि इस वजह से इस रत्न को टाइगर भी कहते हैं। कहते हैं कि टाइगर रत्न धारण करने से सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं।

4. माक्षिक रत्न

माक्षिक रत्न एक खनिज होता है, जो गंधक से मिलकर बना होता है। कहते हैं कि इसे धारण करने से पैसे कमाने के नए-नए तरीके आते हैं। बनावट की बात करें तो यह रत्न शीशे जैसा चमकदार होता है। रत्न शास्त्र के अनुसार, यह रत्न आत्म विश्वास भी पैदा करता है।

5.ग्रीन एवेंच्यूरिन

रत्न शास्त्र में इस स्टोन को व्यापारियों के लिए लाभकारी बताया गया है। कहते हैं कि यह रत्न धन को अपनी ओर आकर्षित करता है और कमाई के नए रास्ते भी बनाता है।

दूसरों की भूलकर भी इन 6 चीजों का न करें इस्तेमाल, आ सकता है भारी संकट

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

अक्सर आपने बड़े-बुजुर्गों से सुना होगा कि कभी दूसरों की चीजों को मांगकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में भी ऐसा करने की मनाही है। वास्तु के अनुसार, कुछ चीजें दूसरों से मांगकर इस्तेमाल करने से हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कहते हैं कि इन छोटी-छोटी चीजों से बड़ा नुकसान हो सकता है। जानिए वास्तु शास्त्र के अनुसार, दूसरों की किन चीजों को मांगकर नहीं करना चाहिए इस्तेमाल-

रुमाल- वास्तु शास्त्र के अनुसार, किसी दूसरे इंसान का रुमाल पास रखने से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। इसे वाद-विवाद से भी जोड़कर देखा जाता है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का रुमाल अपने पास नहीं रखना चाहिए।

घड़ी- वास्तु शास्त्र में घड़ी को सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों से जोड़कर देखा जाता है। कलाई पर किसी दूसरे व्यक्ति की घड़ी को पहनना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति का खराब समय शुरू हो सकता है।

अंगूठी- वास्तु में किसी व्यक्ति की अंगूठी मांगकर पहनना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने व्यक्ति के सेहत, जीवन व आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

पेन- वास्तु शास्त्र के अनुसार, कभी भी किसी व्यक्ति को किसी दूसरे का पेन अपने पास नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से करियर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे धन हानि भी हो सकती है।

कपड़े- वास्तु के अनुसार, कभी भी किसी इंसान को दूसरे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे अंदर नकारात्मकता का प्रवेश होता है और जीवन में मुश्किलें आती हैं।

तुलसी की सूखी पत्तियां चमकाएंगी आपका भाग्य, उन उपायों से मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना भगवान श्रीविष्णु की पूजा पूरी नहीं होती है। मान्यता है कि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में जल देने और उसके सामने दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं तुलसी की सूखी पत्तियों का भी बहुत महत्व है। इसके कुछ ज्योतिष उपाय करने से धन-दौलत की बरसात होती है। वह जातकों को देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

तुलसी की सूखी पत्तियों के उपाय

1. धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रीकृष्ण को तुलसी की सूखी पत्तियां प्रिय हैं। तुलसी की एक पत्ती का इस्तेमाल 15 दिनों तक भगवान कान्हा के भोग में किया जा सकता है।
2. भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप को स्नान करवाते समय तुलसी की सूखी पत्तियों को जल में डाला जा सकता है। वहीं खुद भी पानी में तुलसी के सूखे पत्तों को डालकर स्नान कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है।
3. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की सूखी पत्तियों को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रखें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वह आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
4. तुलसी की सूखी पत्तियों को गंगाजल में डालकर घर में छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। वह परिवार में खुशहाली का वातावरण बना रहता है।

जानिए सिंदूर के प्रभावी उपाय, पैसों की तंगी से लेकर करियर तक हर परेशानी होगी छूमंतर

सिंदूर का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। महिलाएं इससे अपनी मांग भरती हैं। पूजा-पाठ में भी सिंदूर का प्राथमिकता से उपयोग होता है। सिंदूर नारंगी और लाल रंग का होता है। हनुमान जी को नारंगी रंग का सिंदूर चढ़ाया जाता है। टोटके और तंत्र-मंत्र में सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि सिंदूर से किए गए टोटके बेहद असरदायक होते हैं। इसे करने से व्यक्ति की जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती है। आइए जानते हैं सिंदूर के प्रभावी टोटके।

1. संकटों से छुटकारा पाने के लिए और आने वाले मुसिबतों से बचने के लिए हनुमानजी को पांच मंगलवार और 5 शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। गुड और चने के प्रसाद का भोग लगाएं और गरीबों में बांटें।

2. अगर घर में वास्तु दोष है तो दरवाजे पर रोज सुबह सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म होगी। वहीं घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी गणेशी की फोटो भी लगाएं। इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि रहती है।

3. एक पान के पत्ते में फिटकरी और सिंदूर बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबा कर आ जाएं। फिर पीछे पलटकर न देखें। ऐसा 3 बुधवार तक करें। इसे पैसों की आवक बढ़ेगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

4. अगर पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं, तो नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर पूजा करें। मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए नारियल को तिजोरी में रख दें। कुछ ही दिन में आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी।

5. किसी परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता पाना चाहते हैं। गुरु पुष्य योग या शुक्ल पक्ष के पुष्य योग में भगवान गणेश के मंदिर में सिंदूर दान करें।

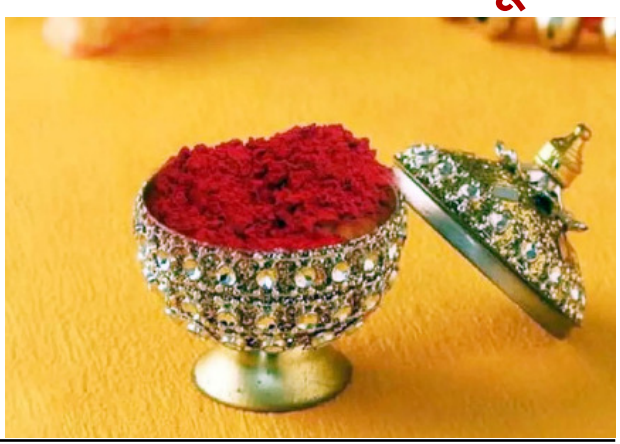

ब्लूस्टोन ने इंदौर में दो ज्वेलरी स्टोर लॉन्च किए, ऑम्नीचैनल मर्चेंडाईजिंग में बड़ी पहल की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

देश के अग्रणी ऑम्नी-चैनल ज्वेलरी रिटेलर, ब्लूस्टोन ने इंदौर में दो स्टोर लॉन्च किए हैं। इनमें से एक स्टोर ए.बी. रोड पर शहर के प्रतिष्ठित लैंडमार्क, स्काईपार्क में और दूसरा स्टोर एम.जी. रोड पर मशहूर बूलवार्ड के सामने स्थित है। इनमें से प्रत्येक स्टोर 1350 वर्गफीट का है, जहां इंदौर के ग्राहकों के लिए खास तौर से बनाए गए डिज़ाईंस का शानदार अनुभव मिलता है। स्टोर का मुख्य आकर्षण यहां का भव्य 'सॉलिटेयर लाउंज' है, जो सॉलिटेयर के प्रशंसकों को खास अनुभव प्रदान करता है। यहां पर विशेषज्ञों और टेक्नॉलॉजी द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म्स की मदद से ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ डिज़ाईन चुनने

में मदद मिलती है।

इस लॉन्च के बारे में ब्लूस्टोन के को-फाउंडर एवं सी. ई. ओ., श्री गौरव सिंह कुशवाहा ने कहा, "इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और खूबसूरती से नक्काशी गई ज्वेलरी के प्रति यहां के प्रेम के कारण इंदौर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। यह मध्य भारत में हमारे लिए एक मुख्य बाजार होगा और हमें अपनी ज्वेलरी निर्माण की कला के आधुनिक एवं समकालीन दृष्टिकोण के लिए विशेषज्ञता स्थापित करने में मदद करेगा।

कंपनी का अवलोकन है कि एक आम ग्राहक किसी स्टोर पर जाने से पहले 2 से 3 हफ्तों तक उसकी वेबसाईट ब्राउज़ करता है। 60 से 70 प्रतिशत ग्राहकों का रूझान ब्रांड के एक्सक्लुसिव स्टोर पर जाने से पहले वेबसाईट पर उत्पाद का चयन करने की ओर होता है। उसके बाद वो स्टोर पर जाकर उत्पाद आजमाकर देखते हैं और फिर चेकआउट करते हैं, इस प्रकार उनका शॉपिंग का अनुभव पूरा होता है। सर्वेक्षण के मुताबिक ब्लूस्टोन से ऑनलाईन खरीद करने वाले हर एक ग्राहक के लिए 20 ग्राहक ऐसे होते हैं, जिन्हें डिज़ाईन पसंद तो होता है, पर वे खरीद करने के लिए स्टोर पर जाना चाहते हैं। इसलिए इन अनुभवात्मक स्टोर्स के माध्यम से ब्लूस्टोन ग्राहकों को एक पूर्णतः ऑम्नीचैनल अनुभव प्रदान करना चाहता है।

डी बीयर्स फॉरएवरमार्क के आइकन ब्राइडल कलेक्शन लांच

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

बात चाहे प्यार को व्यक्त करने की हो या इसमें अटूट विश्वास दिलाने की, डी बीयर्स फॉरएवरमार्क (De Beers Forevermark) का ब्राइडल कलेक्शन आपके साथी के मन में प्यार अंकित करने और हाँ कहलवाने के सबसे सटीक माध्यमों में से एक है। नई शुरुआत के रूप में मनाए जाने वाले त्यौहार, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर, यह ब्रांड डायमंड ज्वेलरी की अनोखी श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। कपल्स द्वारा किए जाने वाले अनमोल वादों से प्रेरित होकर, उन्हें मजबूती देते हुए डी बीयर्स फॉरएवरमार्क प्यार के प्रतीक के रूप में सगाई और शादी के लिए अद्भुत डायमंड रिंग्स की पेशकश करता है, जो हमेशा-हमेशा के लिए साथ रहने वाले कपल्स की

खुशनुमा शुरुआत को चिह्नित करता है। सचिन जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डी बीयर्स इंडिया कहते हैं, 'अक्षय तृतीया को भारतीय कैलेंडर में सबसे शुभ दिन का दर्जा दिया गया है। यह दिन नया काम शुरू करने और रिश्तों की शुरुआत करने वालों के लिए सौभाग्य और सफलता लेकर आता है। किसी विशेष दिन की याद को चिह्नित करने में डायमंड ज्वेलरी विशेष महत्व रखती है। हमें उम्मीद है कि हमारी विशेष रूप से तैयार की गई डायमंड ज्वेलरी कपल्स को विशेष महसूस कराने और साथी से हाँ कहलवाने के रूप में नई और खूबसूरत शुरुआत की प्रतीक बनेंगी और उनके दिन को यादगार बनाने में मददगार साबित होंगी।' कपल्स के बीच रोमांच को बढ़ावा देते हुए ये ज्वेलरी एक अटूट विश्वास वाला रिश्ता कायम करने का हुनर रखती हैं। इन्हें सुंदर बनावट के साथ आज के ज़माने की पसंद को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। डी बीयर्स फॉरएवरमार्क के डायमंड्स की सुंदरता सितारों के बीच चाँद की तरह आकर्षित करती है। भावनात्मक और जीवन को बदल देने वाला शब्द 'हाँ' प्यार की सबसे सार्थक और सामयिक अनुभूति है। एक सदी से भी अधिक समय से डी बीयर्स कपल्स को एक-दूसरे के प्रति इस भावना को साझा करने में मददगार रहा है। डी बीयर्स फॉरएवरमार्क की प्रत्येक सगाई की अँगूठी उस वादे का प्रतिनिधित्व करती है, जो हर रिश्ते के लिए अद्वितीय है।

बीएमडब्लू ग्रुप इंडिया का इंडिया आर्ट फेयर में 'फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी' का प्रदर्शन

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कला और ऑटोमोबाइल्स के बीच अद्वितीय संबंध को दर्शाते हुए बीएमडब्लू ग्रुप इंडिया ने इंडिया आर्ट फेयर के नवीनतम संस्करण में 'फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी' का प्रदर्शन किया। श्री विक्रम पावाहए प्रेसिडेंट, बीएमडब्लू ग्रुप इंडिया के ने कहा कि, 'कला दुनिया के अतीत, वर्तमान और भावी स्वरूप को देखने का एक खूबसूरत माध्यम है। इंडिया आर्ट फेयर कला, रचनात्मकता और लगातार बढ़ती सामाजिक-पर्यावरणीय संवेदनशीलता की चेतना के अद्वितीय मिश्रण का प्रतिबिम्ब है। उसी प्रकार से ठडॅ ग्रुप की प्रवर्तनकारी दृष्टि वाहनों के माध्यम से परिलक्षित होती है। हमारे इलेक्ट्रिक वाहन एक सस्टेनेबल भविष्य की अभिव्यक्ति हैं। जिस प्रकार एक कलाकार किसी केन्द्रीय विषयवस्तु के इर्द-गिर्द अपनी कृति विकसित करता है, ठीक वैसे

ही ठडॅ ग्रुप स्वरूप, प्रकार्य और मनोभाव में सस्टेनेबिलिटी के मूल के इर्द-गिर्द अपने ई-व्हीकल्स विकसित करता है। हम दुनिया के साथ अपनी नई दृष्टिकोण साझा करने के लिए उत्साहित हैं। पहले ही भारत में ऑटो के दीवानों के दिल जीत चुकी हैं। हम हर किसी को आमंत्रित करते हैं कि इंडिया आर्ट फेयर में आ कर हमारे प्रगतिशील ई-मोबिलिटी के स्वरूप का अनुभव करें।' इंडिया आर्ट फेयर के 'प्रेजेंटिंग पार्टनर' के रूप में बीएमडब्लू इंडिया ने वर्ष 2012 से मॉडर्न इंडियन आर्ट और कलाकारों के क्रमिक विकास को आगे बढ़ाया है। इस वर्ष बीएमडब्लू इंडिया अपने ऑल-इलेक्ट्रिक रेंज के विशिष्ट प्रदर्शन से प्रगतिशील ई-मोबिलिटी का प्रदर्शन करेगा। बीएमडब्लू एक्सआई बीएमडब्लू द्वारा प्रस्तुत पहला इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील ड्राइव व्हीकल है। बीएमडब्लू ग्रुप के नये टेक्नोलॉजी फ्लैगशिप के रूप में यह सस्टेनेबिलिटी के प्रति वचनबद्धता के साथ हॉलमार्क 'शीर ड्राइविंग प्लेज़र' का निरूपण है।

दुनिया में अनिश्चितता बढ़ने के बावजूद सोने की मजबूती बरकरार

इंदौर। एजेंसी

दुनिया में सोने के मार्केट की 2022 में शानदार शुरुआत हुई। पहले क्वार्टर की मांग 34 प्रतिशत रही। ईटीएफ फ्लो की मजबूती से यह संभव हुआ। जाहिर है कि भूराजनीतक उथलपुथल और आर्थिक अनिश्चित के दौर में सोने में निवेश करना सबसे सुरक्षित है भू-राजनीतिक संकट की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव आया और ऐसे में निवेशकों ने सोने की ओर रुख किया जिससे इसकी कीमत मार्च में 2,070/ आउंस अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई जो सबसे अधिक थी। वर्ल्ड गोल्ड कौंसिल की ताजा गोल्ड डिमांग ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड ईटीएफ 2020 की तीसरी तिमाही के बाद से 269टी के क्वार्टली इनफ्लो पर है जबकि 2021 में वार्षिक आउटफ्लो 173टी था। यह सोने की कीमत बढ़ने से ही संभव हुआ। इस बारे में लुई स्ट्रीट सीनियर एनेलिस्ट ईएमईए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा 2022 की पहली तिमाही उथलपुथल भरी रही है जिसमें भूराजनीतिक संकट आया, सप्लाई चेन दिक्कत में फंसी और महंगाई भी बढ़ गई इन वैश्विक घटनाओं और बाजार की स्थिति से निवेश के रुप में सोने की सुरक्षित स्थिति और सुदृढ़ हो गई दोहरी प्रकृति की संपत्ति होने की वजह से सोने में निवेश निवेशकों ने ही नहीं बल्कि आम उपभोक्ता ने भी किया बाजार की गतिशीलता के कारण निवेश मांग मजबूत रहने की उम्मीद है क्योंकि महंगाई और भू-राजनीतिक संकट की वजह से सोने की मांग तेज होगी दूसरी ओर आम उपभोक्ता विश्वभर में जीवन लागत बढ़ने के संकट का सामना कर रहे हैं ऐसे में वे अपने खर्च पर पुनर्विचार करेंगे। उपभोक्ताओं की ओर से मांग कोविड के प्रभावों से उबर रही थी। आर्थिक मंदी और कीमतों में वृद्धि से जेवरात की मांग कमजोर पड़ सकती है इस बीच, सोने की बार और सिक्कों की मांग 282टी रही जो पांच साल के औसत से 11प्रतिशत अधिक है। लेकिन चीन में फिर से लॉकडाउन के कारण तुर्की में कीमतें अधिक होने से पिछले साल के मुकाबले 20प्रतिशत कीमत कम हुई। इसकी तुलना में 2021 की पहली तिमाही में काफी मजबूत स्थिति थी जेवरात के सेक्टर में विश्व व्यापी सोने की मांग पिछले साल के मुकाबले 7प्रतिशत गिर कर 474टी पर आ गई। भारत में विवाह की संख्या में गिरावट और शुभ दिनों के अभाव में पहली तिमाही में सोने की खरीदारी पर सीधा असर आया। इसके अलावा, सोने की कीमतों में विश्वभर में उछाल से अनेक भारतीय उपभोक्ताओं ने खरीदारी से अपने हाथ थाम लिए। टैक्नोलॉजी में सोने की मांग 82टी हो गई जो चार साल में सबसे अधिक थी। यह 2021 की पहली तिमाही से 1प्रतिशत ज्यादा है। इस सेक्टर में औसत बढ़ोत्तरी हुई लेकिन यहां भी चुनौतियां कम नहीं थीं। वार्षिक आधार पर सोने की सप्लाई में 4प्रतिशत वृद्धि हुई। खनन उत्पादन बढ़ने से ऐसा हुआ जो 856टी पर पहुंच गया। इसके अलावा रिसाइक्लिंग पिछले साल के मुकाबले 15प्रतिशत बढ़ी औज़र सोने की कीमत बढ़ने के से यह 310टी पर पहुंच गई।

स्पेक्ट्रम आवंटन नीति का यूरोप, 120 देशों के साथ 'तालमेल' बैठाया जाए : सैटकॉम उद्योग

नयी दिल्ली। एजेंसी

उपग्रह संचार उद्योग संगठन एसआईए ने दूरसंचार नियामक ट्राई की स्पेक्ट्रम नीलामी पर सिफारिशों को लेकर चिंता जतायी है। संगठन ने सरकार को पत्र लिखकर स्पेक्ट्रम आवंटन नीति के मामले में यूरोप और 120 से अधिक देशों की नीतियों से तालमेल बनाने का आग्रह किया है। सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसआईए) ने दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की 27.5 से 28.5 गीगाहट्र्ज और 3.60 से 3.67 गीगाहट्र्ज बैंड को प्रस्तावित 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी में शामिल करने की सिफारिशों पर चिंता जतायी है। उद्योग संगठन ने कहा, "यह निश्चित रूप से मौजूदा कंपनियों और उन लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा जो पहले से ही इस बैंड और स्थापित सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। इसमें उपग्रह के माध्यम से प्रसारण, ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने को लेकर पर्याप्त निवेश करने वाले शामिल हैं।" उल्लेखनीय है कि 26 गीगाहट्र्ज और 28 गीगाहट्र्ज बैंड को तकनीकी रूप से मिलीमीटर वेव (एमएम वेव) बैंड कहा जाता है। इसे उच्च 'फ्रीक्वेंसी' दायरा माना जाता है। इसमें प्रेषित सिग्नल कम दूरी को कवर करते हैं लेकिन उनकी गति काफी तेज होती है। एसआईए ने कहा कि सरकार ने मोबाइल सेवा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिये सितंबर, 2021 में कई सुधारों की घोषणा की। इसी तरह, 27.5 से 29.5 गीगाहट्र्ज बैंड की सीमा में फ्रीक्वेंसी को वैश्विक स्तर पर उपग्रहों के लिये संरक्षित रखा जाता है। यहां भी इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संगठन ने कहा, "एक क्षेत्र को दूसरे की कीमत पर बढ़ावा देना संरक्षणवाद हो सकता है।" एसआईए ने कहा कि वैश्विक निकाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) ने 5जी मोबाइल सेवाओं के लिए केवल 26 गीगाहट्र्ज बैंड की पहचान की है। इसमें 28 गीगाहट्र्ज शामिल नहीं है। आईटीयू वैश्विक स्तर पर स्पेक्ट्रम के उपयोग का समन्वय करने के साथ उसे अंतिम रूप देता है। ट्राई ने उपग्रह और मोबाइल सेवाओं के लिए साझा आधार पर 26 गीगाहट्र्ज और 28 गीगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के उपयोग की सिफारिश की है। सैटकॉम उद्योग संगठन ने कहा कि मोबाइल और उपग्रह सेवाओं के लिए 28 गीगाहट्र्ज बैंड के साझा उपयोग पर कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है और इसलिए ऐसा करना भारत के लिये जोखिम भरा होगा। संगठन ने कहा, "भारत को इस संदर्भ में अपनी नीति को लेकर यूरोप और 120 से अधिक देशों से तालमेल बैठाना चाहिए। उन्होंने आईएमटी (इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन) 5 जी और ईएसआईएम (अर्थ सेटेलाइट इन मोशन/फिक्स्ड सेअेलाइट सर्विस) जीएसओ (जियोस्टेशनरी सेटेलाइट ऑर्बिट) और गैर-जीएसओ को अलग-अलग बैंड में बांटा है।" सरकार ट्राई से नीलामी के लिये प्राप्त सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

एमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग पर भारतीय निर्यातक $ 5 बिलियन के करीब

एमेज़ॉन 2025 तक भारत को $20 बिलियन के निर्यात में सक्षम करेगा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग पर 1000 से अधिक भारतीय निर्यातकों ने 2021 की बिक्री में 1 करोड़ रूपए (₹131000) के आंकड़े को पार किया एमेज़ॉन ने आज एक्सपोर्ट्स डाइजेस्ट 2022 का अनावरण करते हुए घोषणा की कि एमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम पर भारतीय निर्यातक द्वारा कुल निर्यात ₹5 बिलियन के जादुई आंकड़े को पार करने की राह पर है। शुरुआत में 1 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने में लगभग 3 साल लगे, परंतु 2 बिलियन डॉलर का लक्ष्य मात्र 17 महीनों में पूर्ण हुआ है। यह कार्यक्रम देश भर में हर आकार के व्यवसायों के बीच उल्लेखनीय रूप से अपनाया जा रहा है और 2015 में इसके लॉन्च होने के बाद से 1 लाख (100ख) से अधिक निर्यातक इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। ये निर्यातक दुनिया भर में यूएसए, यूके, यूएई, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, तुर्की, ब्राजील, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे देशों में एमेज़ॉन की 18 अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइटों के माध्यम से ग्राहकों को लाखों 'मेड इन इंडिया' उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के विकास से उत्साहित होकर, एमेज़ॉन निर्यात को दोगुना करने की प्रतिज्ञा दोहराते हुए 2025 तक भारत को ₹20 बिलियन के निर्यात में सक्षम करेगा।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री नारायण राणे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) ने कहा, 'एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक तिहाई का योगदान करते हैं एवं देश के लगभग आधे निर्यात में एमएसएमई का योगदान है। भारतीय एमएसएमई की निर्यात क्षमता को बढ़ाना एक प्रमुख सरकारी प्राथमिकता है और भारतीय एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी सफलता के लिए समर्थन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। एमएसएमई निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में एमेज़ॉन के निरंतर प्रयास सराहनीय हैं, और 2025 तक 20 बिलियन डॉलर के निर्यात को सक्षम करने की उनकी प्रतिबद्धता समयानुरूप है। मैं एमेज़ॉन और सभी एमएसएमई को 'आत्मानिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करने के लिए निर्यात-आधारित विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बधाई देना चाहता हूं।'

अमित अग्रवाल, एसवीपी इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स, एमेज़ॉन ने कहा, 'हम इस उल्लेखनीय वृद्धि से उत्साहित हैं कि हमारे ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम के माध्यम से 1 लाख से अधिक निर्यातक अच्छा काम कर रहे हैं। 2020 में, एमेज़ॉन ने इस कार्यक्रम का उपयोग करके 2025 तक भारत से कुल निर्यात में ₹10 बिलियन को सक्षम करने का वादा किया था। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिये, भारतीय एमएसएमई को जल्दी ही यह समझ में आया कि ई-कॉमर्स उनके लिए वैश्विक स्तर पर ग्राहकों तक पहुंचना आसान बनाता है। हम दुनिया भर में मेड इन इंडिया उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग में शामिल होने वाले निर्यातकों की संख्या में तेजी से वृद्धि देख रहे हैं। इसलिए हम 2025 तक ई-कॉमर्स का उपयोग करके भारत से निर्यात को ₹20 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने की अपनी प्रतिज्ञा को बढ़ा रहे हैं। हम भारतीय एमएसएमई के लिए निर्यात को आसान बनाने के लिए सभी प्रमुख हितधारकों के साथ काम करना जारी रखेंगे ताकि उन्हें मजबूत व्यवसाय बनाने और भारत से वैश्विक ब्रांड बनाने में मदद मिल सके।'

रिजर्व बैंक के नीतिगत दर बढ़ाने के निर्णय से डूबा बाजार, सेंसेक्स 1,307 अंक लुढ़का

मुंबई। शेयर बाजारों में दोपहर कारोबार में तेज गिरावट आई और दोनों मानक सूचकांक...बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी...दो प्रतिशत से अधिक लुढ़क कर बंद हुए। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अचानक रेपो दर बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत करने की घोषणा के बाद बाजार में गिरावट आई।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,306.96 यानी 2.29 प्रतिशत लुढ़क कर 55,669.03 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह एक समय 1,474.39 अंक तक नीचे चला गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 391.50 अंक यानी 2.29 प्रतिशत टूटकर 16,677.60 अंक पर बंद हुआ।

रिजर्व बैंक ने रेपो दर 0.40 प्रतिशत बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय किया। मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। खुदरा महंगाई दर पिछले तीन महीने से लक्ष्य की ऊपरी सीमा छह प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तय कार्यक्रम के बिना हुई की बैठक में सभी छह सदस्यों ने आम सहमति से नीतिगत दर बढ़ाने का निर्णय किया। दूसरी तरफ उदार रुख को भी कायम रखा गया है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार के विजयकुमार ने कहा, ''बिना पूर्व कार्यक्रम के एमपीसी की बैठक में रेपो दर में 0.40 प्रतिशत और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 0.50 प्रतिशत की वृद्धि 'चौंकाने' वाली है, क्योंकि यह कदम उस दिन उठाया गया, जिस दिन एलआईसी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम खुला है।'' उन्होंने कहा, ''देश के सबसे बड़े आईपीओ के पहले दिन सेंसेक्स में 1,000 अंक से अधिक की गिरावट ने धारणा को प्रभावित किया है।'' सेंसेक्स के शेयरों में टाइटन, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, मारुति और डॉ. रेड्डीज सर्वाधिक नुकसान में रहे। दूसरी तरफ पावरग्रिड, एनटीपीसी और कोटक महिंद्रा बैंक लाभ में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 3.12 प्रतिशत उछलकर 108.3 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 1,853.46 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।

भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते के विस्तार पर बात की

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते के विस्तार पर बुधवार को चर्चा की। इससे दोनों देशों के बीच और उड़ानों के संचालन का रास्ता साफ होगा। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अमेरिका और कनाडा के नौ दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने कनाडा के परिवहन मंत्री उमर अल्घाब्रा से बुधवार को मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अल्घाब्रा ने ट्वीट किया, ''महामारी की शुरुआत में भारत में फंसे कनाडाई नागरिकों को वापस भेजने में भारत से हमें जो मदद की गई उसके लिए मैंने अपने भारतीय समकक्ष को निजी तौर पर आभार व्यक्त किया।'' कनाडा की आबादी में भारतवंशी लोगों की अच्छी खासी संख्या है। अल्घाब्रा ने कहा कि कनाडा और भारत के लिए पारस्परिक महत्व वाले मुद्दों पर उनकी सिंधिया के साथ सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने कहा, ''हमने हवाई परिवहन समझौते के विस्तार के बारे में बात की जिससे दोनों देशों के बीच और उड़ानों का संचालन हो सकेगा।'' उन्होंने कहा कि अमृतसर तक उड़ान समेत दोनों देशों के बीच उड़ान सेवा के विस्तार के लिए वह और बातचीत करने को उत्सुक हैं।

करीब पौने चार साल बाद रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरें बढ़ाईं, रेपो में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.40 प्रतिशत बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया। मुख्य रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। खुदरा मुद्रास्फीति पिछले तीन महीने से लक्ष्य की उच्चतम सीमा छह प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। आरबीआई को खुदरा महंगाई दर दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है।

तय कार्यक्रम के बिना हुई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में सभी छह सदस्यों ने आम सहमति से नीतिगत दर बढ़ाने का निर्णय किया। दूसरी तरफ उदार रुख को भी कायम रखा गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई दर लक्ष्य की ऊपरी सीमा छह प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। अप्रैल महीने में भी इसके ऊंचे रहने की संभावना है। मार्च महीने में खुदरा मुद्रास्फीति 6.9 प्रतिशत रही। रिजर्व बैंक ने अगस्त, 2018 के बाद पहली बार नीतिगत दर में बढ़ोतरी की है।

बिजली क्षेत्र की मजबूत मांग के बीच अप्रैल में कोयले का उत्पादन 28 प्रतिशत बढ़ा

नयी दिल्ली। देश के कई हिस्सों में बिजली संकट के बीच अप्रैल में देश का कोयला उत्पादन 28 प्रतिशत बढ़कर 6.61 करोड़ टन हो गया। उल्लेखनीय है कि हाल के समय में ताप बिजली संयंत्रों की कोयले की मांग भी बढ़ी है।

अप्रैल, 2021 में कुल कोयला उत्पादन 5.16 करोड़ टन रहा था।

कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''अप्रैल, 2022 के दौरान भारत का कुल कोयला उत्पादन 661.54 लाख टन था।'' कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी अनुषंगी कंपनियों ने पिछले महीने 5.34 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया, जबकि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा 53 लाख टन और खुद के इस्तेमाल वाली (कैप्टिव) खानों द्वारा 73 लाख टन कोयला उत्पादन किया गया।

कोयला मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, जहां महीने के दौरान कोयला क्षेत्र का कुल उठाव 7.08 करोड़ टन था, वहीं बिजली क्षेत्र का उठाव अप्रैल में 6.17 करोड़ टन तक पहुंच गया। वहीं, अकेले कोल इंडिया से बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 4.97 करोड़ टन रही। बिजली उत्पादन संयंत्रों से शुष्क ईंधन की ऊंची मांग के मद्देनजर सीआईएल द्वारा बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति पिछले महीने में वार्षिक आधार पर 15.6 प्रतिशत अधिक थी। कोयला मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि वह आने वाले महीनों में विशेष रूप से बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ाएगा। कोल इंडिया का घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। सरकार ने पहले कहा था कि मौजूदा बिजली संकट मुख्य रूप से विभिन्न ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन में तेज गिरावट के कारण है, न कि घरेलू कोयले की अनुपलब्धता के कारण। कोयला सचिव ए के जैन ने बिजली संयंत्रों में कम कोयले के स्टॉक की स्थिति के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के बाद के दौर में अर्थव्यवस्था में तेजी लौटने के कारण बिजली की मांग बढ़ी है और गर्मियां जल्दी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा गैस और आयातित कोयले के दाम में बढ़ोतरी तथा तटीय ताप बिजलीघरों का उत्पादन घटने की वजह से भी बिजली संकट की स्थिति बनी है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।